THE RESEARCH DIALOGUE
An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
© The Research Dialogue | Volume-04 | Issue-04 | January-2026
Available online at: https://theresearchdialogue.com/
DOI: : https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v4i4.10

कृषि के वाणिज्यीकरण का ग्रामीण समाज पर प्रभाव

(जनपद अयोध्या के हैरिंगटनगंज विकासखंड पर आधारित एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

डा0 सन्तराम पाल

असि0 प्रो0 समाजषास्त्र विभाग, आ0 न0 दे0 किसान पी0 जी0 कालेज, बभनान-गोण्डा (उ0 प्र0)

सारांश :

"भारतीय ग्रामीण समाज की मुख्य आधारशिला कृषि रही है।"[1] परंपरागत भारतीय कृषि-व्यवस्था निर्वाह-उन्मुखी थी जिसमें उत्पादन का उद्देश्य पारिवारिक उपभोग तथा स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। किंतु, "औपनिवेशिक काल से प्रारंभ होकर स्वतंत्रता के पश्चात हरित-क्रांति के जन्म, तकनीकी विकास, बाज़ार विस्तार, वैश्वीकरण और सरकारी नीतियों के साझे परिणामस्वरूप कृषि का वाणिज्यीकरण तीव्र गति से हुआ।"[2] कालांतर में "इस प्रक्रिया ने ग्रामीण समाज में न केवल आर्थिक, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और संरचनात्मक परिवर्तन भी उत्पन्न किए।"[3] प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य कृषि के वाणिज्यीकरण के ग्रामीण समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। अध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या के हैरिंगटनगंज विकासखंड को क्षेत्रीय इकाई के रूप में चुना गया है। यह क्षेत्र कृषि-प्रधान है जहाँ छोटे, सीमांत एवं मध्यम किसानों की बहुलता है तथा परंपरागत और आधुनिक कृषि प्रणालियाँ साथ-साथ विद्यमान हैं। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कृषि के वाणिज्यीकरण ने जहाँ उत्पादन, आय और बाज़ार संपर्क को बढ़ाया है, वहीं सामाजिक असमानता, वर्ग-विभाजन, भूमिहीनता, पलायन, पारिवारिक विघटन और सांस्कृतिक परिवर्तन जैसी समस्याओं को भी जन्म दिया है।

मुख्य शब्द: कृषि का वाणिज्यीकरण, ग्रामीण समाज, सामाजिक परिवर्तन, हैरिंगटनगंज, अयोध्या

भूमिका:

भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ की विशाल जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संरचना का विकास ऐतिहासिक रूप से कृषि के इर्द-गिर्द हुआ है। परंपरागत ग्रामीण समाज में कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं थी बल्कि सामाजिक संगठन, जाति-व्यवस्था, पारिवारिक संरचना और सांस्कृतिक मूल्यों का भी आधार थी। ग्रामीण-जीवन सामुदायिक-सहयोग, पारस्परिक-निर्भरता और आत्मनिर्भरता पर आधारित था। परंतु, समय के साथ-साथ औद्योगीकरण, नगरीकरण, तकनीकी विकास और बाज़ार आधारित व्यवस्था ने कृषि को भी गहराई से प्रभावित किया। औपनिवेशिक शासन के दौरान नगदी फसलों की खेती, लगान की व्यवस्था और निर्यातोन्मुख कृषि-नीतियों ने कृषि के स्वरूप को बदलना प्रारंभ किया। स्वतंत्रता के पश्चात हरित-क्रांति ने कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की। किंतु, इसके सामाजिक परिणाम भी अत्यंत गहरे रहे। सामान्यतः कृषि का वाणिज्यीकरण इसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। हैरिंगटनगंज विकासखंड, जो कि जनपद अयोध्या का एक प्रमुख ग्रामीण क्षेत्र है, कृषि के वाणिज्यीकरण के प्रभावों को समझने के लिए चुना गया है। यहाँ कृषि आज भी जीवन का मुख्य आधार है। किंतु, पारंपरिक कृषि व्यवस्था अब धीरे-धीरे बाज़ारोन्मुख कृषि में परिवर्तित हो रही है।

अध्ययन की पृष्ठभूमि:

"भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया औपनिवेशिक काल से प्रारंभ मानी जाती है।"[4] ब्रिटिश शासन ने भारतीय कृषि को ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगदी फसलों—जैसे नील, कपास, जूट और गन्ना—की खेती को बढ़ावा दिया। इससे किसानों की आत्मनिर्भरता समाप्त हुई और वे बाज़ार तथा साहूकारों पर निर्भर होते चले गए। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्य ने कृषि विकास को प्राथमिकता दी। हरित-क्रांति ने आधुनिक-तकनीक, उन्नत-बीज, रासायनिक उर्वरक और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया। इससे उत्पादन तो बढ़ा, किंतु इसका लाभ मुख्यतः बड़े और संसाधन-सम्पन्न किसानों को ही मिला। कृषि के वाणिज्यीकरण ने ग्रामीण समाज को आर्थिक रूप से गतिशील तो बनाया है किंतु इसके साथ-साथ कई सामाजिक समस्याएँ भी उत्पन्न हुई हैं। ग्रामीण समाज में वर्गीय विभाजन, भूमिहीनता, ऋणग्रस्तता, पारंपरिक संबंधों का विघटन और ग्रामीण-पलायन जैसी समस्याएँ उभरकर सामने आई हैं परिणामस्वरूप ग्रामीण समाज में वर्गीय असमानता और क्षेत्रीय विषमता बढ़ने लगी। शोध-क्षेत्र हैरिंगटनगंज विकासखंड में भी यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। यहाँ कृषि उत्पादन अब केवल उपभोग के लिए नहीं, बल्कि बाज़ार में बिक्री और लाभ अर्जन के लिए किया जा रहा है। । हैरिंगटनगंज विकासखंड के संदर्भ में यह जानना आवश्यक है कि कृषि के वाणिज्यीकरण ने विभिन्न सामाजिक वर्गों और समुदायों को किस प्रकार प्रभावित किया है? इन्हीं तथ्यों को समझने के लिए प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य रखे गये हैं-

1. कृषि के वाणिज्यीकरण की अवधारणा को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से स्पष्ट करना।
2. हैरिंगटनगंज विकासखंड में कृषि के वाणिज्यीकरण की प्रकृति का अध्ययन करना।
3. ग्रामीण सामाजिक संरचना पर इसके प्रभावों का विश्लेषण करना।
4. वर्ग, जाति और पारिवारिक व्यवस्था में आए परिवर्तनों को समझना।
5. ग्रामीण जीवन-शैली और सांस्कृतिक मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अनुसंधान पद्धति का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर संकलित तथ्यों का समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के आलोक में गुणात्मक विश्लेषण किया गया है। प्राथमिक स्रोतों में कृषकों, कृषि-मजदूरों और ग्रामीण निवासियों से साक्षात्कार एवं अवलोकन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया गया है और द्वितीयक आंकड़ों में पुस्तकें, शोध-पत्र, सरकारी रिपोर्टें, जनगणना आँकड़े इत्यादि को सम्मिलित किया गया है।

कृषि के वाणिज्यीकरण की अवधारणा:

कृषि का वाणिज्यीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कृषि उत्पादन का उद्देश्य आत्मनिर्भरता से हटकर बाज़ार में बिक्री और लाभ अर्जन बन जाता है। इसमें नगदी फसलों की खेती, कृषि-यंत्रीकरण, रासायनिक आदानों का प्रयोग और बाज़ार से गहरा जुड़ाव शामिल होता है। **डार्लिंग** के अनुसार- "जब किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बजाय बाज़ार के लिए उत्पादन करने लगे, तो कृषि वाणिज्यीकृत कहलाती है।"[4] मार्क्सवादी दृष्टिकोण से यह प्रक्रिया पूँजीवादी संबंधों के विस्तार को दर्शाती है जबकि वेबर इसे तर्कसंगतता और बाज़ार अर्थव्यवस्था से जोड़ते हैं। प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र हैरिंगटनगंज विकासखंड में गेहूँ, धान, गन्ना और दलहन प्रमुख फसलें हैं। आँकड़ों के अनुसार हाल के वर्षों में गन्ना और सब्ज़ियों जैसी नगदी फसलों की खेती बढ़ी है। कृषि-यंत्रीकरण और उन्नत-तकनीक के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई है किंतु लागत भी बढ़ी है।

कृषि के वाणिज्यीकरण के मुख्य कारण:

कृषि के वाणिज्यीकरण के प्रमुख कारणों में तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक कारणों को समझा जाता है। तकनीकी कारणों में हरित-क्रांति, उन्नत बीजों एवं उर्वरकों का चलन, कृषि-यंत्रीकरण इत्यादि।आर्थिक कारणों में बाज़ार की माँग, नकद आय की आवश्यकता, कृषि ऋण एवं सरकारी योजनाएँ इत्यादि और सामाजिक कारणों में जीवन स्तर में वृद्धि की आकांक्षा, शिक्षा और उपभोक्तावाद, नगरीय प्रभाव इत्यादि को समझा जाता है।

कृषि के वाणिज्यीकरण का **ग्रामीण सामाजिक संरचना पर प्रभाव[5]:**

1. सामाजिक संबंधों में परिवर्तन-

कृषि के वाणिज्यीकरण से ग्रामीण समाज में पारंपरिक सेवा-आधारित संबंध का विघटन हुआ और उसकी जगह किसानों व श्रमिकों के बीच अधिक औपचारिक, संविदात्मक (contractual) संबंध विकसित हुए। सहयोगात्मक एवं पारंपरिक संबंधों के स्थान पर आर्थिक एवं औपचारिक संबंधों का विकास हुआ है। जजमानी प्रथा एवं पारस्परिक सहायता की भावना कमजोर हुई है तथा लाभ आधारित व्यवहार बढ़ा है। कृषि के वाणिज्यीकरण ने ग्रामीण सामाजिक संबंधों को पारंपरिक, सहयोगात्मक और भावनात्मक स्वरूप से हटाकर औपचारिक, आर्थिक और व्यावसायिक बना दिया है। यद्यपि इससे आर्थिक अवसर बढ़े हैं परंतु सामाजिक एकता एवं सामुदायिक भावना कमजोर हुई है। अतः संतुलित ग्रामीण विकास के लिए सामाजिक मूल्यों के संरक्षण की भी आवश्यकता है।

2. जाति व्यवस्था पर प्रभाव-

कृषि के वाणिज्यीकरण ने ग्रामीण समाज में जाति आधारित कार्य-विभाजन को प्रभावित किया है। उच्च जातियों के बड़े किसान आर्थिक रूप से अधिक सशक्त हुए जबकि निम्न जातियाँ कृषि मजदूर के रूप में सीमित होती गईं। आर्थिक स्थिति ने सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित करना शुरू किया जिससे जातीय कठोरता में कुछ कमी आई किंतु असमानता बनी रही। कृषि के वाणिज्यीकरण ने जाति और पेशे के पारंपरिक संबंध को आंशिक रूप से कमजोर किया है। अब सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति बनती जा रही है यद्यपि जातीय असमानताएँ अब भी विद्यमान हैं और इनमे कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आयी है।

3. वर्ग-विभाजन व आर्थिक असमानतामें वृद्धि-

कृषि के वाणिज्यीकरण से ग्रामीण समाज में धनी किसान और जमींदार जो नकदी फसलों के उत्पादन का जोखिम उठा सकते थे उन्होंने खूब मुनाफा कमाया जबकि छोटे किसान कर्ज के जाल में फंसकर भूमिहीन हो गए जिससे ग्रामीण समाज में वर्ग-भेद बढ़ गया। किसान वर्ग का स्पष्ट विभाजन हुआ—बड़े किसान, मध्यम किसान छोटे एवं सीमांत किसान,भूमिहीन मजदूर। इससे सामाजिक संरचना में वर्गीय-असमानता बढ़ी है। वाणिज्यीकरण का लाभ मुख्यतः बड़े और मध्यम किसानों को हुआ है। छोटे और सीमांत किसान महंगे बीज, उर्वरक और मशीनों के कारण कर्ज़ग्रस्त हो गए हैं। इससे ग्रामीण समाज में वर्गीय विभाजन और आर्थिक असमानता बढ़ी है। ग्रामीण समाज में बड़े जमींदारों के साथ-साथ अब एक बड़ा वर्ग भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का बन गया जो अपनी आजीविका के लिए बड़े किसानों पर निर्भर हैं इसने ग्रामीण समाज में कृषि-संबंधों की संरचना को पुनर्परिभाषित करने का कार्य किया है

4. पारिवारिक संरचना पर प्रभाव-

कृषि के वाणिज्यीकरण से ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार व्यवस्था की व्यवस्था कमजोर हुई है। बढती आबादी और निजी संपत्ति की अवधारणा ने भूमि-विभाजन की प्रवृत्ति को बढाया है। व्यक्तिगत लाभ की प्रवृत्ति और नगद आय के महत्व से एकल परिवारों की संख्या बढ़ी है और पारिवारिक संबंध अधिक औपचारिक हुए हैं। आर्थिक दबाव और रोजगार की कमी के कारण ग्रामीण युवाओं का शहरों की ओर पलायन बढ़ा है। इससे संयुक्त परिवार व्यवस्था कमजोर हुई है और एकल परिवारों की संख्या बढ़ी है। परिवार में पारंपरिक कर्ता की भूमिका अब क्षीण हो गई है जबकि आर्थिक रूप से सबल करता की भूमिका बढ़ी है।

5. सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि-

कृषि का वाणिज्यीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कृषि उत्पादन का उद्देश्य आत्मनिर्भरता से हटकर बाज़ार एवं लाभ अर्जन हो जाता है। इस परिवर्तन ने भारतीय ग्रामीण समाज की संरचना को प्रभावित किया है और विशेष रूप से सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया है। कृषि के वाणिज्यीकरण ने सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया है। आर्थिक रूप से सफल किसान सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने लगे हैं। अब सामाजिक स्थिति केवल जन्म पर नहीं, बल्कि आर्थिक शक्ति पर भी निर्भर होने लगी है। कृषि के वाणिज्यीकरण ने ग्रामीण समाज में सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया है। आर्थिक सफलता अब सामाजिक प्रतिष्ठा का महत्वपूर्ण आधार बन गई है। हालाँकि यह गतिशीलता सभी वर्गों के लिए समान नहीं है, फिर भी यह ग्रामीण समाज में परिवर्तन एवं विकास का एक महत्वपूर्ण संकेत है।

6. महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव-

महिलाओं की कृषि कार्यों में भागीदारी बनी रही, किंतु वाणिज्यीकरण के बावजूद—निर्णय लेने की शक्ति पुरुषों के पास रही, महिलाओं का श्रम अक्सर अदृश्य एवं अवैतनिक बना रहा हालाँकि कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक जागरूकता बढ़ी है। वाणिज्यीकरण के कारण महिलाओं की भागीदारी कृषि श्रम में बढ़ी है किंतु निर्णय-निर्माण में उनकी भूमिका अभी भी सीमित है। इससे महिला श्रम का शोषण बढ़ा है। कृषि और घरेलू कार्यों के दोहरा बोझ के कारण महिलाओं के पास समय की कमी और शारीरिक थकावट बढ़ गई है। कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग बढ़ने से महिला श्रमिकों में चर्म रोग, सिरदर्द, और सांस संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ गया है। भूमि स्वामित्व ऋण और कृषि तकनीकों तक महिलाओं की पहुँच अभी भी बहुत सीमित है जिससे उन्हें पुरुष किसानों के मुकाबले नुकसान उठाना पड़ता है। समान कार्य के बावजूद, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। महिलाओं के योगदान को अक्सर मान्यता नहीं मिलती विशेषकर पारिवारिक खेतों में काम करते समय यद्यपि व्यवसायीकरण ने महिलाओं को आर्थिक अवसर और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान की है, लेकिन असमान भूमि अधिकार, कम तकनीकी पहुँच और अत्यधिक श्रम भार उनके वास्तविक सशक्तिकरण में मुख्य बाधाएं बनी हुई हैं।

7.ग्रामीण संस्कृति पर प्रभाव-

कृषि के वाणिज्यीकरण से ग्रामीण समाज में उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास हुआ, मुद्रा और नकदी की मांग बढ़ने लगी जिससे परंपरागत रीति-रिवाजों का ह्रास और ग्रामीण समाज में नगरीय जीवन शैली का प्रभाव अब साफ देखने को मिलता है। ग्रामीण समाज में उपभोगवादी संस्कृति और नगरीय जीवन-शैली का प्रभाव बढ़ा है। पारंपरिक सादगी, सामुदायिकता और नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है जिससे ग्रामीण समाज में रूपांतरण की प्रक्रिया तीव्र हुई है। अब लोग आत्मनिर्भरता से बाजार निर्भरता की ओर बढ़ने लगे हैं।

8.भूमि-संबंधों में परिवर्तन-

परंपरागत भारतीय ग्रामीण समाज में भूमि केवल आजीविका का साधन नहीं थी बल्कि, यह सामाजिक प्रतिष्ठा, सुरक्षा और शक्ति का आधार भी थी। कृषि के वाणिज्यीकरण के साथ जब खेती लाभ और बाज़ार-उन्मुख हो गई तब, भूमि-संबंधों में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलने लगा। भूमि अब केवल आजीविका का साधन न रहकर आर्थिक संपत्ति बन गई है। भूमि का संकेंद्रण बढ़ने से भूमिहीन कृषि मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई है। कृषि के वाणिज्यीकरण ने भूमि-संबंधों को परंपरागत, भावनात्मक और संरक्षणवादी स्वरूप से बदलकर आर्थिक, औपचारिक और बाज़ार-आधारित बना दिया है। इससे जहाँ कृषि उत्पादकता और पूँजी निवेश बढ़ा है, वहीं भूमि असमानता और ग्रामीण सामाजिक तनाव भी बढ़े हैं। संतुलित ग्रामीण विकास के लिए भूमि सुधार और छोटे किसानों के संरक्षण की व्यापक आवश्यकता है।

निष्कर्ष: उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कृषि के वाणिज्यीकरण ने ग्रामीण सामाजिक संरचना को व्यापक रूप से परिवर्तित किया है जहाँ इसने आर्थिक विकास और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक असमानता, वर्ग-विभाजन और पारंपरिक मूल्यों के क्षरण

जैसी समस्याएँ को भी जन्म दिया है। कृषि के वाणिज्यीकरण ने ग्रामीण समाज की पारंपरिक और सामुदायिक संरचना को कमजोर कर किया है। पहले कृषि कार्य सामूहिक सहयोग से होते थे किंतु अब वे व्यक्तिगत लाभ और प्रतिस्पर्धा पर आधारित हो गए हैं। इससे ग्रामीण सामाजिक संबंधों में औपचारिकता और स्वार्थपरकता बढ़ी है। अतः आवश्यक है कि कृषि विकास की नीतियाँ सामाजिक संतुलन एवं न्याय को ध्यान में रखकर बनाई जाएँ। कृषि का वाणिज्यीकरण ग्रामीण समाज के लिए एक जटिल और द्वैध प्रक्रिया है। हैरिंगटनगंज विकासखंड का अध्ययन स्पष्ट करता है कि -"कृषि का वाणिज्यीकरण ग्रामीण समाज के जहाँ आर्थिक विकास के अवसर प्रदान करती है, वहीं सामाजिक असमानता, वर्ग विभाजन और सांस्कृतिक विघटन जैसी समस्याएँ भी उत्पन्न करती है।"[6] अतः आवश्यक है कि कृषि विकास नीतियों को सामाजिक न्याय और संतुलित ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण से लागू किया जाए जिससे टिकाऊ और समावेशी विकास को गति दी जा सके।

सन्दर्भ सूची:

1. देसाई, ए. आर.(1969): भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र, मुंबई, पॉपुलर प्रकाशन।
2. दत्त, के. एल.(1998): कृषि विकास और सामाजिक परिवर्तन, नई दिल्ली, विकास पब्लिशिंग हाउस।
3. धनागरे, डी. एन.(2004): भारतीय समाजशास्त्र में दृष्टिकोण, जयपुर, रावत पब्लिकेशन्स।
4. Srinivas, M.N.(1966): Social Change in Modern India, Uni. of California Press,USA
5. Thorner, D.(1956): The Agrarian Prospect in India, Delhi University Press, Delhi.
6. उत्तर प्रदेश के ग्रामीण आँकड़े(2021): अयोध्या जनपद हस्तपुस्तिका, नई दिल्ली।

Cite this Article:

डा0 सन्तराम पाल," कृषि के वाणिज्यीकरण का ग्रामीण समाज पर प्रभाव (जनपद अयोध्या के हैरिंगटनगंज विकासखंड पर आधारित एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)" The Research Dialogue, Open Access Peer-reviewed & Refereed Journal, Pp.85–89.

This is an Open Access Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.

CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

डा0 सन्तराम पाल

For publication of Research Paper title

कृषि के वाणिज्यीकरण का ग्रामीण समाज पर प्रभाव

(जनपद अयोध्या के हैरिंगटनगंज विकासखंड पर आधारित एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-04, Issue-04, Month January, Year-2026, Impact Factor (RPRI-4.73)

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor- In-chief

Dr. Neeraj Yadav
Executive-In-Chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at: https://theresearchdialogue.com/

DOI: : https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v4i4.10